## चीनी डिकंट्रोल पर राय मांगी

केंद्र ने चीनी उद्योग पर लगे नियंत्रण हटाने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में केंद्र ने राज्य सरकारों से इस माह के अंत तक रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट पर राय मांगी है। चीनी उद्योग पर इस समय कई तरह की पाबंदियां लगी हैं। इसमें चीनी की खुले बाजार में बिक्री और सरकार द्वारा सस्ते मूल्य पर लेवी चीनी खरीदना शामिल है।

पहल ◆ चीनी उद्योग के डिकंट्रोल पर केंद्र सरकार की सक्रियता

# चीनी उद्योग के लिए कमेटी के सुझावों पर राज्यों से राय मांगी

### नवंबर के अंत तक राज्यों से सुझाव लेकर दिसंबर में फैसले की तैयारी

प्रेट्र • नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग पर लगे नियंत्रण हटाने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में केंद्र ने राज्य सरकारों से इस माह के अंत तक रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट पर राय मांगी है।

चीनी उद्योग पर इस समय कई तरह की पाबंदियां लगी हैं। इसमें चीनी की खुले बाजार में बिक्री और सरकार द्वारा सस्ते मूल्य पर लेवी चीनी खरीदना शामिल है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने चीनी उद्योग को डिकंट्रोल करने के लिए रंगराजन रिपोर्ट पर राज्यों से उनके विचार मांगे हैं। इस रिपोर्ट पर राज्यों की सहमति काफी अहम है। राज्यों से इस माह के अंत तक अपने सुझाव देने को कहा गया है।

उद्योग पर लगी पाबंदियां हटाने के बारे में सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सी. रंगराजन की अगुवाई में विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया था।

कमेटी ने कई सिफारिशें करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी थी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के प्रमुख रंगराजन की अगुवाई वाली कमेटी ने बिक्री में कोटा प्रणाली और लेवी चीनी व्यवस्था तुरंत खत्म करने की सिफारिश की थी।

उद्योग लंबे अरसे से कंट्रोल हटाने की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि नियंत्रण हटाए जाएं तो उद्योग की सालाना विकास दर 15 से 20 फीसदी तक हो जाएगी और नया निवेश बढ़ाया जा सकेगा।

हाल में खाद्य मंत्री के. वी. थॉमस ने कहा था कि सरकार आगामी दिसंबर तक रंगराजन रिपोर्ट पर फैसला करेगी। रिपोर्ट में गन्ने का खरीद मूल्य निर्धारण करने और मिलों का 70 फीसदी राजस्व किसानों को देने की भी सिफारिश की है। हालांकि कमेटी की इस सिफारिश से गन्ना उत्पादक किसानों को संभवतः कम कीमत मिल सकेगी क्योंकि अभी उन्हें मौजूदा गन्ना मूल्य पर चीनी मिलों का 80 फीसदी तक राजस्व मिल रहा है।

रंगराजन ने सिफारिश की है कि मिलों से 10 फीसदी चीनी सस्ती कीमत पर लेवी के रूप में लेने की व्यवस्था खत्म की जाए। सरकार इस चीनी का वितरण सस्ते मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीब उपभोक्ताओं को करती है।

कमेटी ने मिलों के लिए रिजर्व गन्ना क्षेत्र की व्यवस्था खत्म करने और दो मिलों के बीच का दायरा घटाने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई है। इससे मिलों को फिलहाल गन्ना खरीद में स्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा और किसानों को किसी अन्य मिल को गन्ना बेचने का विकल्प अभी नहीं मिल पाएगा।

### वैश्विक स्तर पर चीनी का सरप्लस स्टॉक ज्यादा

लंदन • इंटरनेशनल शुगर ऑर्गनाइजेशन (आईएसओ) ने मौजूदा मार्केटिंग वर्ष 2012-13 के दौरान वैश्विक स्तर पर 61.8 लाख टन सरप्लस स्टॉक होने का अनुमान पेश किया है। आईएसओ का कहना है कि मौजूदा सीजन के अंत तक चीनी के मूल्य में सुस्ती का रुख जारी रह सकता है। आईएसओ का ताजा सरप्लस स्टॉक अनुमान पिछले अनुमान से ज्यादा है। इससे पहले उसने 58.6 लाख टन सरप्लस स्टॉक की संभावना जताई थी। हालांकि पिछले साल के सरप्लस स्टॉक 69.9 लाख टन से ताजा स्टॉक अनुमान कम है। (प्रेट्र)

### मिलों को फायदा

- खुले बाजार में बिक्री का कोटा हटने से ज्यादा मुनाफा संभव
- लेवी चीनी व्यवस्था खत्म होने से भी वित्तीय दबाव कम होगा

### किसानों पर असर

- 70 फीसदी राजस्व हिस्सेदारी से घट सकता है गन्ने का मूल्य
- रिजर्व एरिया अभी जारी रहने से गन्ना बेचने का विकल्प नहीं